



## विमुद्रीकरण का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

KEY WORDS:

'डॉ० रंजना नीलिमा  
कच्छप

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

## ABSTRACT

जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करके नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक, काला धन वापस लाना, कर चोरी पर प्रतिबंध, एवं आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना होता है। विमुद्रीकरण के इतिहास से पता चलता है कि अफ्रीकी देश घाना, नाइजिरिया, म्यांमार, सोवियत संघ आदि देशों ने विमुद्रीकरण का कदम उठाया पर सफलता नहीं मिल पायी। भारत में भी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा कदम माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उठाया तथा एक ही बार में 86 प्रतिशत मुद्रा जो 500 रु एवं 1000 रु के रूप में अर्थव्यवस्था में चलन में थे बंद करने की घोषणा की। फलस्वरूप अध्ययन एवं आंखों देखी खबर से पता चलता है कि पूरे देश में अफरा-तफरी का आलम नजर आने लगा अर्थव्यवस्था लगभग थोड़े समय के लिए थम सी गयी। लोग मुद्रा के पीछे भागते हुए नजर आये। इससे डिजिटल लेन-देन में वृद्धि हुई, कर चोरी कम हुई एवं राजकोषीय आय में वृद्धि हुई। दूसरी ओर गरीबों व किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा साथ ही आर्थिक विकास दर में कमी के साथ अर्थव्यवस्था में मंदी देखी गयी। नोटबंदी के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिले।

## अध्ययन का उद्देश्य –

1. विमुद्रीकरण के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना।
2. विमुद्रीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना।

## प्रस्तावना

जब सरकार पुरानी मुद्रा (currency) को कानूनी तौर पर बंद कर देती है एवं नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी देश में काले धन की एक समानान्तर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है एवं जाली मुद्रा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तब नोटबंदी अर्थात् विमुद्रीकरण किया जाता है जिसके अंतर्गत वर्तमान मुद्रा को तत्काल प्रभाव से बंद कर नई मुद्रा जारी की जाती है। प्राचीन काल के आचार्य चाणक्य से लेकर आधुनिक काल के भीमराव अम्बेडकर तक ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था का मुख्य चरण बताया है। जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नवजीवन की उत्पत्ति होती है।

## विमुद्रीकरण का इतिहास—

1946 में 500 एवं 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जाँच से जुड़ी वांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था किन्तु सुझाव सार्वजनिक होने के कारण नोटबंदी नहीं हो पायी।

1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 एवं 10,000 के नोट बंद कर दिये। हलाकि तत्कालीन गवर्नर आई जी पटेल ने इस नोट बंदी का विरोध किया था।

विश्व के आधुनिक इतिहास में नोटबंदी का कदम सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना में उठाया गया था। 1982 में टैक्स चोरी व भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से 50 SD के नोटों को बंद कर दिया गया था। इससे वहाँ के नागरिकों को अपने ही देश की मुद्रा से विश्वास उठ गया था। वहाँ की जनता ने विदेशी मुद्रा एवं जमीन जायदाद का रूख लिया जिससे न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को नुकसान पहुँचा बल्कि विदेशी मुद्रा पर काला बाजारी बढ़ गया।

1984 में नाइजिरिया ने कदम उठाये परिणामस्वरूप कर्ज में डूबी व महंगाई तले दबी अर्थव्यवस्था को राहत नहीं मिल पायी थी।

1987 में म्यांमार कालाबाजार को काबू में करने के उद्देश्य से 80 फीसदी मुद्रा को अघोषित कर दिया इस कदम के प्रति जनता में काफी नाराजगी एवं गुस्सा दिखाई दिया और यह सफल नहीं हो पाया।

2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 के पहले के 500 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था।

8 नवम्बर 2016 को भारत देश में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एकाएक 500 रु एवं 1000 रु के नोट बंद करने की घोषणा की। सरकार द्वारा देश की जनता को पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए समय सीमा भी दी गयी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ रु मूल्य के बराबर नोट बाजार में थे जिनमें से करीब 14.18 लाख करोड़ रु 500 एवं 1000 के नोटों के रूप में थे। अर्थात् कुल रूपयों का लगभग 86 फीसदी हिस्सा अचानक बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप धनी वर्गों से लेकर राजनीतिज्ञ, आतंकवादियों, नक्सलियों तथा हवाला कारोबारियों में अफरा-तफरी मच गयी। इतना बड़ा कदम विश्व के इतिहास में पहली बार उठाया गया।

## अध्ययन का उद्देश्य –

1. विमुद्रीकरण के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना।
2. विमुद्रीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक अध्ययनों पर आधारित है।

## पूर्व शोध-पत्रों एवं विचारों का अध्ययन –

1. पिकी रमोल, डा० विवेक नेगी – इन्होंने "विमुद्रीकरण एक पैलियेटिव या प्लेसबो" विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि विमुद्रीकरण से न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे विश्व में रूपये की स्वीकार्यता एवं प्रतिष्ठा में निश्चित ही तेज गिरावट आयी है। यद्यपि विमुद्रीकरण का निर्णय अपरिहार्य रूप से आर्थिक व लोक प्रशासन के वैश्विक सिद्धांतों के रूप में पूर्णतः विफल रहा है। पांच राज्यों के चुनाव पर जो परिणाम आये वो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन का उद्देश्य कठोर कदमों के माध्यम से नहीं बल्कि अधिनियमों, कानूनों और नियमों के सरलीकरण से हासिल किया जा सकता है।
2. डी० सुब्बाराव – रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी० सुब्बाराव ने कहा कि नोटबंदी का पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। इन्होंने कहा कि अल्पकाल के लिए 500 एवं 1000 के नोटों पर पाबंदी वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। यदि सरकार और रिजर्व बैंक जितनी तेजी एवं प्रभावी तरीके से स्थिति के प्रबंधन में सफल रहता है उसका उतना ही कम विपरित प्रभाव पड़ेगा। नई मुद्रा के चलन में आने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
3. डॉ० प्रणव मुखर्जी – राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नोटबंदी के फैसले पर पहले दिन से ही सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार को आगाह किया कि नोटबंदी की वजह से गरीबों की परेशानियाँ बढ़ी हैं इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से सहायता मुहैया करायी जाय।

## विमुद्रीकरण के उद्देश्य –

विमुद्रीकरण के संबंध में आम धारणा यह है कि पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा जारी की जाती है, पर अपनी नजरों से अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल की स्थिति पहली बार देखने को मिला अतः मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न होने लगी कि किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोदी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया तथा सामान्य जन-जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। अध्ययन से उपलब्ध जानकारी –

1. कालाधन समाप्त करने के लिए – सामान्य तौर पर पर्दे के पीछे हुए लेन-देन को हम काला धन कहते हैं। चूंकि 86 फीसदी रूपये 500 एवं 1000 के नोट के रूप में थे तो अधिकांश लोगों ने काला धन के रूप में इन नोटों को अपने पास रखा होगा। इस घोषणा से काला धन अवैध हो जायेगा एवं उसे वैध करने के लिए लोग विभिन्न तरह के उपाय अपना सकते हैं।
2. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए – भारतीय उद्योग परिषद (सी०सी०आई०) ने कहा कि विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे कई दशकों से जड़ जमाए भ्रष्टाचार से निपटने में सहायता मिलेगी एवं इसमें कमी आयेगी।
3. नकली नोटों को चलन से बाहर करना – नोटबंदी का एक उद्देश्य यह भी है कि जो नकली नोट चलन में ला रहे हैं उनके पास भी 500 एवं 1000 के नकली नोट होंगे वह भी एकाएक बंद हो जायेगा जिससे वह चलन से बाहर हो जायेगा।
4. आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए – अर्थव्यवस्था से 86 प्रतिशत मुद्रा अवैध घोषित कर दिया गया। देश में आतंकवादी गतिविधियों भी इन्हीं मुद्राओं के जरिए फल-फूल रहे थे, नोटबंदी होने से इन गतिविधियों पर भी रोक लगायी जा सकेगी।
5. नगद लेन-देन को हतोत्साहित करना – अर्थव्यवस्था में सरकार जनता से एकाएक 86 फीसदी मुद्रा अपने हाथ में ले रही है इससे जनता के हाथों नगद

मुद्रा कम हो गयी। जिससे लेन-देन हतोत्साहित हुआ एवं बाजार में क्रय एवं विक्रय में मंदी देखी गयी।

### विमुद्रीकरण के प्रभाव

- विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव –**
  - देश में शांति का वातावरण निर्मित** – मुद्रा के कारण जो अशांति फैली थी वह रूक सी गयी थी। देश में आतंकी, नक्सली सब ठंडे पड़ चुके थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कश्मीर में शांति का माहौल दिखाई दे रहा था।
  - जाली नोटों का चलन बंद** – विमुद्रीकरण से जाली नोटों का चलन बंद हो जायेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
  - जनता का बैंकों के प्रति जागरूकता में वृद्धि** – नोटबंदी के बाद कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने कभी एटीएम से पैसे नहीं निकाले थे अब वो एटीएम से पैसे निकालना सीख रहे थे तथा कई लोग बैंक नहीं जाते थे अब बैंक जाने लगे थे। इससे जनता में बैंकों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई।
  - कर की चोरी पर रोक** – हमारे आंखों देखे हाल हैं। इतने वर्षों से कई व्यावसायी एवं लोग भी अपनी आय कम बताकर कम टैक्स देते थे। जिससे सरकार को कम आय की प्राप्ति होती थी। अब नोटबंदी से अपने पास जमा धन बैंकों में जमा करने के साथ टैक्स भी देने पड़ रहे हैं। 2016 में साढ़े तीन करोड़ लोगों के पास ही पैसों का कित्ना एक साल में इसकी संख्या बढ़कर 33 करोड़ हो गयी। 23 लाख 50 हजार करदाताओं की संख्या 22 हजार 173 करोड़ रुपये टैक्स वसूली टॉरगेट तथा 3 लाख 50 हजार नोटबंदी के बाद करदाता जुड़े यह स्थिति छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की है। इससे सरकार को आय की प्राप्ति होगी एवं देश का विकास होगा।
  - डिजिटल लेन-देन में वृद्धि** – नोटबंदी के कारण जनता के हाथों से नगद मुद्रा छिन सी गयी है। अपनी आवश्यकता की चीजें भी लेने के लिए नगद मुद्रा नहीं थी। ऐसी स्थिति में जनता का रुझान डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक साल में डेढ़ गुना वृद्धि देखी गयी। नोटबंदी के पहले 2016 में 70.21 करोड़ सौदे डिजिटल लेन-देन से हुए थे लेकिन बाद में यह लगभग 113 करोड़ पहुंच गयी।
  - राजकोषीय घाटे में कमी** – विमुद्रीकरण से लोगों के हाथों से पैसा बैंक में जमा हो रहा है एवं जमा धन जिसका पहले कोई लेखा-जोखा नहीं था। अब टैक्स सहित बैंक में जमा होने लगे हैं जिससे राजकोषीय धन में वृद्धि देखी जा रही है जिससे घाटे में कमी आ रही है। कुल कर राजस्व 18 प्रतिशत से बढ़कर 17.1 लाख करोड़ पहुंच गया।
  - सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की संभावना** – नोटबंदी से सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत 65 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में प्राप्त हो सकता है। जिसका उपयोग आधारभूत ढांचे के निर्माण में किया जा सकता है।
  - चुनावों में धन का प्रभाव कम होगा क्योंकि नगद मुद्रा की कमी है।
  - मजदूर वर्ग खुश था क्योंकि उसका शोषण करने वाले मालिक का काला धन बाहर आ रहा था।
  - नोटबंदी के बाद 100 दिनों में 2.26 करोड़ नए जनधन खाते खुले तथा तीन महीनों में 19084 करोड़ रुपये खातों में जमा हुए।

### विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभाव –

- अस्थायी मंदी** – विमुद्रीकरण से जनता के हाथों से नगद मुद्रा ले लिए जाने पर कारोबार एवं व्यवसाय पर विपरित असर दिखाई दे रहा है। जनता द्वारा लेन देन न करने के कारण व्यापारियों के कारोबार में भी सुस्ती नजर आयी एवं कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे मानो अर्थव्यवस्था थम सी गयी है।
- गरीबों के हित में नहीं** – निम्न तमके के लोगों के पास पहले से ही नोटों की कमी रहती है। किसी प्रकार वे अपना गुजारा करते हैं। नगद मुद्रा भी छिन जाने पर उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एटीएम से भी 2000 के नोट निकलने से जिनके पास कुल 2000 रुपये भी न हो तो वह कहां से पैसे लाये साथ ही जिसने पैसे निकाल भी लिए तो वस्तुओं को क्रय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
- बेरोजगारी में वृद्धि** – नोटबंदी का व्यापार, व्यवसाय, कारोबार सभी पर विपरित प्रभाव पड़ने के कारण कई लोगों का रोजगार छिन गया। बेरोजगारों के पास काम नहीं होने से आर्थिक तंगी सामने आ रही है साथ ही छोटे कारोबारियों का धंधा प्रभावित होने के कारण वे भी बेरोजगार हो गये। अर्थव्यवस्था में नोटबंदी के बाद बेरोजगारी में भी वृद्धि देखी गयी।
- निजि क्षेत्र में गिरावट** – आईएचएस मार्केट की अर्थशास्त्री एवं सर्वे रिपोर्ट तैयार करने वाली पॉलीयाना डी. लीमा ने कहा कि भारतीय सर्विस सेक्टर के लिए 2016 का अंत काफी धीमा रहा है। पीएमआई इंडेक्स के संकेतानुसार इस क्षेत्र की कंपनियों में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की औसत गतिविधियां साल 2014 की शुरुआत के बाद न्यूनतम स्तर पर आ गयी हैं।
- विकास दर का घटना** – नोटबंदी के कारण वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अर्थात् आर्थिक विकास दर घटकर 7.1 फीसदी का अनुमान लगाया गया पर बाद में यह 6.7 फीसदी ही रही। जबकि 2016 में यह 8 फीसदी था।
- ग्रामीणों का शोषण** – ग्रामीणों को डिजिटल लेन देन की जानकारी नहीं होने के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के खातों से उनकी जानकारी के बिना पैसे दूसरे निकाल ले गये। इस तरह आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
- जाली नोटों का चलन बंद न होना** – कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे

जाली नोटों का चलन बंद हो गया पर अर्थव्यवस्था में जाली नोटों का चलन बंद नहीं हुआ पुनः 500 एवं 2000 के जाली नोटों का चलन प्रारंभ हो गया।

- कृषक वर्ग पर विपरित प्रभाव** – किसान वर्ग दुखी था क्योंकि वह अपनी फसल के लिए बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाईयों को रुपये के अभाव में आसानी से नहीं खरीद पा रहा था। संचित पूंजी भी खतरे में नजर आ रही थी क्योंकि लोगों का खाता बैंक में नहीं था।
- महिलाओं की बचत प्रवृत्ति पर विपरित प्रभाव – महिलाओं द्वारा छिपाकर 500 व 1000 के नोट जो बचाकर रखे गये थे उस पर विपरित प्रभाव पड़ा। बचत राशि बैंक में जमा करनी पड़ी जो अब तक सही लाइन नहीं पा सकी।
- पर्यटन उद्योग पर विपरित प्रभाव** – नोटबंदी के कारण पर्यटन उद्योग पर विपरित प्रभाव पड़ा क्योंकि विदेशी सैलानियों की आवक देश में कम देखी गयी।
- हाउसिंग लोन की ग्रोथ में कमी आयी, ब्याज दर में कमी आयी।

### निष्कर्ष –

विमुद्रीकरण से पूरी अर्थव्यवस्था में उत्थल-पुथल सी मच गयी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था में नव जीवन की उत्पत्ति हुई है। इससे डिजिटल लेन-देन में वृद्धि हुई, कर चोरी पर प्रतिबंध, बैंकों के प्रति जागरूकता, राजकोषीय घाटे में कमी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आदि के रूप में सकारात्मक प्रभाव पड़े एवं कृषक वर्ग, पर्यटन उद्योग, ग्रामीणों का शोषण, विकास दर का घटना, बेरोजगारी में वृद्धि, निजी क्षेत्रों में गिरावट के रूप में नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अर्थतंत्र में सारे काम काज प्रभावित हुए हैं पर धीरे धीरे नई मुद्रा के चलन में आने से अर्थव्यवस्था में गति आती दिखाई दे रही है ऐसा माना जा रहा है कि नोट बंदी से संगठित क्षेत्र का विस्तार होगा एवं दीर्घकाल में इसके फायदे देश को मिलेंगे। वर्तमान में नकदी पर अंकुश एवं कर अनुपालन में सुधार से सरकार का खजाना भरता नजर आ रहा है। अपैल से अक्टूबर के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 15.2 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई है।

### सुझाव –

- छोटे नोटों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए** – सरकार को छोटे नोटों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। ताकि नगद मुद्रा गरीब उपभोक्ता के हाथों तक पहुंच सके। जिससे वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की चीजों को खरीद सकें।
- रोजगार उन्मूलन कार्यक्रमों पर व्यय** – रोजगार उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक व्यय करना चाहिए जिससे बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके एवं पैसे गरीबों के हाथों तक पहुंच सके। शायद मनरेगा पर 38 हजार करोड़ से 48 हजार करोड़ रुपये बजट में देने की यही मंशा सरकार की है।
- डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को जागरूक करना** – डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे आसानी से एवं स्वयं द्वारा लेन-देन कर सकें एवं किसी भी प्रकार से शोषण के शिकार न हों।
- घ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कानूनों व नियमों का सरलीकरण किया जाना आवश्यक है।**

### संदर्भ ग्रंथ

- नई दुनिया, 6 जनवरी 2017, पेज नं 0 1 एवं 06। 8 नवम्बर 2017 पेज नं 0 2।
- नवभारत, 2 जून 2017, पेज नं 4। 8 नवम्बर 2017 पेज नं 0 1।
- दैनिक भास्कर, 8 नवम्बर 2017 पेज नं 0 1।
- अग्रवाल, प्रमोद कुमार, (2016,) उदय इंडिया, विमुद्रीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
- <http://khabar.ndtv.com>
- <http://www.bbc.com/hindi/india-37974344>